	1987	1988
	राशियां (रुपए)	राशियां (रुपए)
(क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में प्रति ऋण खाता औसत राशि	8184	8561
(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रति ऋण खाता औसत राशि . .	3767	4157

उपर्युक्त स्थिति से यह देखा जा सकता है कि 1987 की तुलना में 1988 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति खातों की संख्या और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को संवितरित राशि दोनों में तदनुरूप वृद्धि हुई थी । इसी प्रकार, संदर्भाधीन अवधि के दौरान प्रति खाता संवितरित औसत राशि में भी वृद्धि हुई है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों के लिए ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आदेश दिया है कि उनके कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों के लिए होना चाहिए । इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों के लिए उपयुक्त बैंक योग्य योजनाएं तैयार करने के वास्ते विशेष प्रयास किए जाने चाहिए । तदनुसार, वाणिज्यिक बैंक, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग लेते हैं ताकि पता लगाए गए हिताधिकारी अपने आर्थिक उत्थान के लिए सक्षम योजनाएं अपनाने में समर्थ हो सकें । उपर्युक्त के अलावा, बैंक भी समाज के कमजोर वर्गों को उत्पादक उद्यमों के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराके सहायता पहुंचाने के वास्ते स्वयं योजनाएं बनाते हैं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों को ऋण सहायता प्रदान करने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है और पाई गई कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं ।

Gold prices and its supply from Government mints

895. SHRI RAM JETHMALANI:
SARDAR JAGJIT SINGH AURORA:
SHRI YASHWANT SINHA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem published in the Hindustan Times of 16th December, 1991 captioned "Gold smuggling gets going against";

(b) if so, whether it is a fact that smuggling of gold has become a profitable profession following the sharp rise in the prices of gold in the country;

(c) if so, what were the prices of gold in the international market in December, 1991 and January, 1992 respectively;

(d) whether it is also a fact that supply of gold from the Mints including the mint in Bhagat Singh Road, Souty Bombay had been stopped during these months;

(e) if so, what was the total quantity of gold requisitioned from the Mint at that time;

(f) what was the quantity of gold supplied during these months for domestic and export purposes and what were the reasons for not supplying gold as per the requisition;

(g) what remedial measures Government is taking in the matter;

(h) what is the effect of the non-supply of gold by SBI on export of jewellery; and

(i) what are the details of remedial measures taken by Government in order to boost the export of jewellery?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (i) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

NRIs suggestion on liberalisation for augumenting their investment in India

896. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the NRIs have suggested further liberalisation in the economic fiscal and trade policies and reviewing of FERA regulations to enable them to make adequate investments in India;

(b) if so, what is the reaction of Government thereon;

(c) whether Government have offered any other inducements to NRIs for investments in India; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) Suggestions for liberalisation are received from NRIs from time to time. These are kept in view while formulating policy.

(c) and (d) Under the liberalised investment policy, NRIs can now invest upto 100 per cent equity in high priority industries with full repatriation benefits. They can also invest in housing, real estate and infrastructure sectors on a repatriation basis. The upper limit on portfolio investment by NRI in Indian companies has also been raised, subject to certain conditions, from 5 per cent to 24 per cent.

विदेशी ऋणों पर अदा की गई ब्याज की राशि

897. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 दिसम्बर, 1991 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डब्टर : ओ. ई. सी. डी." शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विदेशी ऋण पर 1980–81, 1985–86 और 1991–92 के वर्षों के दौरान अलग-अलग कितनी ब्याज राशि का भुगतान किया गया है ;

(ग) क्या विदेशी ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की दर भिन्न-भिन्न देशों अथवा संस्थाओं के अनुसार अलग-अलग होती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्याज की न्यूनतम तथा अधिकतम दर कितने प्रतिशत है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1980–81 और 1985-86 के दौरान विदेशी ऋण पर अदा किए गए ब्याज की राशि क्रमश: 412 करोड़ रुपए और 1592 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1991-92 के दौरान अदा किए जाने वाले ब्याज की राशि